



न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर (199)

प्र0क0 111/निगरानी/श्योपुर/भू0रा0/2017/2562

- 1-नबाबउददीन
 - 2-मकसूद
 - 3-मंजूर
 - 4-मजहर
 - 5-मुजफ्फर
- समस्त पुत्रगण निजामुद्दीन जाति मुसलमान निवासी ग्राम वालापुरा तहसील व जिला श्योपुर (म0प्र0)
-आवेदक

श्री ~~श्रीकृष्ण चामर लाल~~
द्वारा आज दि. 4-8-17 को प्रस्तुत

4-8-17
कलक ऑफ कोर्ट
गुजरात राजस्व मण्डल ग्वालियर

बनाम

- 1-शब्बीर पुत्र निजामुद्दीन निवासी ग्राम वालापुरा तह0 व जिला श्योपुर
- 2-वसीरम पत्नी निजामुद्दीन
- 3-हसीना पुत्री निजामुद्दीन निवासी ग्राम वालापुरा तह0 व जिला श्योपुर म0प्र0

.....असल/अनावेदक

निगरानी विरुद्ध आदेश दिनांक 20/07/2017

न्यायालय श्रीमान अपर आयुक्त महोदय चम्बल

संभाग मुरैना के प्र0क0 248/अपील/निगरानी

अन्तर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता

श्रीमान जी,

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में निम्नलिखित प्रस्तुत है -

- 1- यह कि ग्राम वालापुरा तह0 व जिला श्योपुर में स्थित कृषि भूमि सर्वे क0 1681/3 ख रकवा 2 बीघा के आवेदकगण व अनावेदकगण क0 1 व 3 के पिता तथा अना0 क0 2 के पति निजामुद्दीन भूमि स्वामी होकर आधिपत्यधारी थे।

- 2- यह कि निजामुद्दीन की मृत्यु दिनांक 10/04/2014 को हो जाने पर अना0 क0 1 द्वारा वसियत के आधार पर तहसीलदार महोदय श्योपुर के समक्ष दिनांक 10/07-08 X अ/6 पर

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक तीन/निगरानी/शोपुर/भूरा/2017/2562

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिमा' आदि के हस्ताक्षर
25 -9-17	<p>आवेदक के अधिवक्ता श्री श्रीकृष्ण शर्मा उपस्थित होकर उनके द्वारा अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना के प्रकरण क्रमांक 248/अपील/2016-2017 में पारित आदेश दिनांक 20.7.17 के विरुद्ध म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।</p> <p>2- आवेदक के अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया तथा प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया गया। अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय के प्रकरण क्रमांक 10/अ-6/2007-08 में पारित आदेश दिनांक 28.12.2007 के परिप्रेक्ष्य में अनुविभागीय अधिकारी शोपुर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जो अवधि बाह्य थी जिसे मानने में कोई त्रुटि नहीं की गई है और इसकी पुष्टि अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना द्वारा अपने आदेश में की गई है। अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना के प्रकरण क्रमांक 248/अपील/2016-2017 में पारित आदेश दिनांक 20.7.17 उचित होने से हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं समझता हूँ। आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से अग्राह की जाती है।</p>	